Think IAS...

दृष्टि The Vision

Think Drishti

संघ लोक सेवा आयोग (UPSC)

भारतीय अर्थव्यवस्था

(भाग–2)

दूरस्थ शिक्षा कार्यक्रम (Distance Learning Programme)

Code: CSPM07

दृष्टि The Vision

संघ लोक सेवा आयोग (UPSC)

भारतीय अर्थव्यवस्था

(भाग–2)

दृष्टि The Vision

641, प्रथम तल, डॉ. मुखर्जी नगर, दिल्ली-110009
दूरभाष : 8750187501, 011-47532596
टोल फ्री : 1800-121-6260
Web : www.drishtiias.com
E-mail : online@groupdrishti.com

पाठ्यक्रम, नोट्स तथा बैच संबंधी updates निरंतर पाने के लिए निम्नलिखित पेज को "like" करें
www.facebook.com/drishtithevisionfoundation
www.twitter.com/drishtiias

UPSC DLP

विषय सूची (Contents)

6.	लोक वित्त	5–34
7.	कर संरचना	35–81
8.	आयोजन	82–141
9.	निवेश मॉडल एवं पूंजी निर्माण	142–166
10.	श्रम सुधार एवं जनांकिकीय	167–197
11.	व्यष्टि अर्थशास्त्र	198–232
12.	पूंजी बाज़ार	233–288

अध्याय
6

लोक वित्त
(Public Finance)

6.1 अर्थ एवं परिभाषा
6.2 लोक वित्त की विषय-सामग्री
6.3 लोक वित्त एवं निजी वित्त
6.4 लोक वित्त का महत्त्व
6.5 सार्वजनिक वस्तुएँ बनाम निजी वस्तुएँ
6.6 राजकोषीय नीति
6.7 राजकोषीय नीति के उद्देश्य
6.8 बजट
6.9 घाटे का बजट की विभिन्न अवधारणाएँ/प्रकार
6.10 बजट में सुधार
6.11 घाटे की वित्त व्यवस्था या हीनार्थ प्रबंधन
6.12 विनिवेश
6.13 राजकोषीय समेकन
6.14 व्यय प्रबंधन आयोग
6.15 सार्वजनिक ऋण
6.16 सार्वजनिक ऋण प्रबंधन इकाई और लोक ऋण प्रबंधन एजेंसी
6.17 राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम, 2003

6.1 अर्थ एवं परिभाषा *(Meaning and Definition)*

लोक वित्त अर्थशास्त्र की वह शाखा है जो सरकार के आय-व्यय का अध्ययन करती है अर्थात् लोक वित्त का संबंध केंद्र सरकार, राज्य सरकार एवं स्थानीय सरकार के आय एवं व्यय से होता है। लोक वित्त का संबंध लोक सत्ताओं की वित्तीय व्यवस्था के विज्ञान एवं कला से होता है। विभिन्न अर्थशास्त्रियों ने लोक वित्त को भिन्न-भिन्न प्रकार से परिभाषित किया है-

डॉ. डाल्टन के अनुसार, "लोक वित्त उन विषयों में से एक है जो अर्थशास्त्र एवं राजनीति शास्त्र की सीमा रेखा पर स्थित है। इसका संबंध लोक सत्ताओं के आय-व्यय तथा उनके पारस्परिक समायोजन और समन्वय से है।

प्रो.सी.एल. बैस्टेल के अनुसार, 'लोक वित्त राज्य की लोक सत्ताओं के आय-व्यय, उनके पारस्परिक संबंध, वित्तीय प्रशासन एवं नियंत्रण का अध्ययन करता है। समग्रता से लोक वित्त मूल रूप से सरकारों के आय-व्यय से संबंधित है तथा सरकारों का अर्थ केंद्र सरकार, राज्य सरकारों तथा स्थानीय सरकारों से है। वर्तमान में लोक वित्त का क्षेत्र अधिक व्यापक हो गया है, इसके अंतर्गत सरकार के आय-व्यय के अतिरिक्त वित्तीय प्रशासन, लेखा निरीक्षण, सार्वजनिक ऋण प्रबंधन एवं वित्तीय नियंत्रण आदि कार्यों को भी सम्मिलित किया जाता है-

6.2 लोक वित्त की विषय-सामग्री *(Subject Matter of Public Finance)*

लोक वित्त के विभिन्न पहलुओं की विवेचना इतिहास में भी मिलती है। एडम स्मिथ ने अपनी पुस्तक 'Wealth of Nation' (1776) के खंड 5 में लोक वित्त के विभिन्न अंगों का विश्लेषण किया है। इस खंड में तीन अध्याय हैं जो क्रमशः सरकार के व्यय, सरकार के राजस्व तथा लोक ऋण का विवेचन करते हैं। लोक वित्त अर्थशास्त्र का वह भाग है जो किसी देश की वित्त व्यवस्था तथा उससे संबंधित प्रशासनिक एवं अन्य समस्याओं का अध्ययन करता है और अंततः इसका उद्देश्य स्थिरता के साथ आर्थिक विकास की गति को बनाए रखना होता है। लोक वित्त के अध्ययन को निम्नलिखित भागों में विभाजित किया जा सकता है-

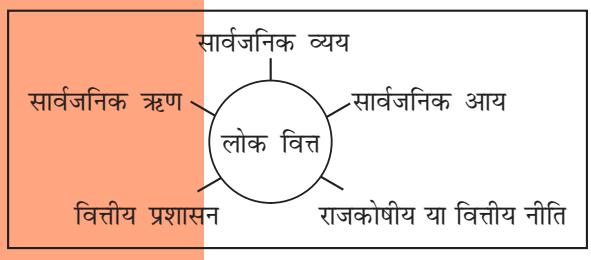

- समिति ने यह देखा है कि राष्ट्रीय आपदा, राष्ट्रीय सुरक्षा या फिर अन्य अपवादस्वरूप परिस्थितियों में (जो कि एफआरबीएम अधिनियम में उल्लिखित हैं) सरकार अपने निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करने में असफल रहती है। समिति ने सुझाया कि सरकार को लक्ष्यों की प्राप्ति में विचलित होने के आधारों को स्पष्ट करना चाहिये।
- राजकोषीय परिषद की सलाह पर सरकार कुछ निर्धारित परिस्थितियों में अपने निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति से विचलित हो सकती है, जैसे-
  - राष्ट्रीय सुरक्षा, युद्ध, राष्ट्रीय आपदा, कृषि उत्पादन और आय में गिरावट।
  - वित्तीय प्रभावों के परिणामस्वरूप अर्थव्यवस्था में संरचनात्मक सुधार।
  - वास्तविक उत्पादन वृद्धि में गिरावट पिछली 4 तिमाहियों के 3 प्रतिशत से कम हो। यह अंतर एक वर्ष में जीडीपी के 0.5 प्रतिशत से ज़्यादा न हो।
- प्रस्तुत बिल सरकार को कुछ निश्चित परिस्थितियों को छोड़कर आरबीआई से उधार लेने से रोकता है, जैसे-
  - जब सरकार की प्राप्तियों में क्षणिक गिरावट आ जाती है।
  - आरबीआई सरकारी प्रतिभूतियों की खरीद द्वितीयक बाज़ार से करे।

बहुविकल्पीय प्रश्न

1. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिये:

UPSC (Pre) 2018

1. राजकोषीय दायित्व और बजट प्रबंधन (एफ.आर.बी.एम.) समीक्षा समिति के प्रतिवेदन में सिफारिश की गई है कि वर्ष 2023 तक केंद्र एवं राज्य सरकारों को मिलाकर ऋण-जी.डी.पी. अनुपात 60% रखा जाए जिसमें केंद्र सरकार के लिये यह 40% तथा राज्य सरकारों के लिये 20% हो।
2. राज्य सरकारों के जी.डी.पी. के 49% की तुलना में केंद्र सरकार के लिये जी.डी.पी. का 21% घरेलू देयतायें हैं।
3. भारत के संविधान के अनुसार यदि किसी राज्य के पास केंद्र सरकार की बकाया देयताएँ हैं तो उसे कोई भी ऋण लेने से पहले केंद्र सरकार से सहमति लेना अनिवार्य है।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

(a) केवल 1 (b) केवल 2 और 3
(c) केवल 1 और 3 (d) 1, 2 और 3

2. साल-दर-साल लगातार घाटे का बजट रहा है। घाटे को कम करने के लिये सरकार द्वारा निम्नलिखित में से कौन-सी कार्रवाई/कार्रवाइयाँ की जा सकती है/हैं?

UPSC (Pre) 2016

1. राजस्व व्यय को घटाना
2. नवीन कल्याणकारी योजनाओं को प्रारंभ करना
3. सहायिकी (सब्सिडी) को युक्तिसंगत बनाना
4. आयात शुल्क को कम करना

नीचे दिये गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिये:

(a) केवल 1 (b) केवल 2 और 3
(c) केवल 1 और 3 (d) 1, 2, 3 और 4

3. निम्नलिखित में से किसको/किनको भारत सरकार के पूंजी बजट में शामिल किया जाता है?

UPSC (Pre) 2016

1. सड़कों, इमारतों, मशीनरी आदि जैसी परिसंपत्तियों के अधिग्रहण पर व्यय
2. विदेशी सरकारों से प्राप्त ऋण
3. राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों को अनुदत्त ऋण और अग्रिम

नीचे दिये गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिये:

(a) केवल 1 (b) केवल 2 और 3
(c) केवल 1 और 3 (d) 1, 2 और 3

4. वर्ष-प्रतिवर्ष निरंतर घाटे का बजट रहा है। घाटे को कम करने के लिये सरकार द्वारा निम्नलिखित में से कौन-सी कार्रवाई/कार्रवाइयाँ की जा सकती है/हैं?

UPSC (Pre) 2015

1. राजस्व व्यय में कमी लाना
2. नई कल्याणकारी योजनाएँ आरंभ करना
3. उपदानों (सब्सिडीज़) का युक्तीकरण करना
4. उद्योगों का विस्तार करना

नीचे दिये गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिये:
(a) केवल 1 और 3 (b) केवल 2 और 3
(c) केवल 1 (d) 1, 2, 3 और 4

5. संघ के बजट के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन-सा/से गैर-योजना व्यय के अधीन आता है/आते हैं? **UPSC (Pre) 2014**
1. रक्षा व्यय 2. ब्याज अदायगी
3. वेतन एवं पेंशन 4. उपदान
नीचे दिये गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिये:
(a) केवल 1 (b) केवल 2 और 3
(c) 1, 2, 3 और 4 (d) कोई नहीं

6. भारत में घाटे की वित्त व्यवस्था किसके लिये संसाधनों को बढ़ाने के लिये उपयोग की जाती है? **UPSC (Pre) 2013**
(a) आर्थिक विकास के लिये
(b) सार्वजनिक ऋण चुकाने के लिये
(c) भुगतान शेष का समायोजन करने के लिये
(d) विदेशी ऋण कम करने के लिये

7. निम्नलिखित में से किस एक का अपने प्रभाव में सर्वाधिक स्फीतिकारी होने की संभावना है? **UPSC (Pre) 2013**
(a) लोक ऋण की चुकौती।
(b) बजट घाटे के वित्तीयन के लिये जनता से ऋणादान।
(c) बजट घाटे के वित्तीयन के लिये बैंकों से ऋणादान।
(d) बजट घाटे के वित्तीयन के लिये नई मुद्रा का सृजन।

8. निम्नलिखित में से किस/किन परिस्थिति/परिस्थितियों में 'पूंजीगत लाभ' हो सकता है? **UPSC (Pre) 2012**
1. जब किसी उत्पाद के विक्रय में वृद्धि हो।
2. जब किसी संपत्ति के मूल्य में प्राकृतिक वृद्धि हो।
3. जब आप कोई रंगचित्र खरीदें और उसकी लोकप्रियता बढ़ने के कारण उसके मूल्य में वृद्धि हो।
निम्नलिखित कूटों के आधार पर सही उत्तर चुनिये:
(a) केवल 1
(b) केवल 2 और 3
(c) केवल 2
(d) 1, 2 और 3

9. भारत सरकार केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों (CPSEs) में लगी अपनी इक्विटी का विनिवेश क्यों कर रही है? **UPSC (Pre) 2011**
1. सरकार अपनी इक्विटी के विनिवेश से मिले राजस्व का उपयोग मुख्यत: अपने बाह्य ऋण को लौटाने में करना चाहती है।
2. सरकार अब CPSEs के प्रबंधन का नियंत्रण अपने हाथों में नहीं रखना चाहती।
उपर्युक्त में से कौन-सा/से कथन सही है/हैं?
(a) केवल 1 (b) केवल 2
(c) 1 और 2 दोनों (d) न तो 1 और न ही 2

10. निम्नलिखित में से कौन-सा एक राजकोषीय उत्तरदायित्व तथा बजट प्रबंधन अधिनियम, 2003 (फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट एक्ट, 2003) में अनुबद्ध नहीं है? **UPSC (Pre) 2010**
(a) राजकोषीय वर्ष 2007-08 की समाप्ति तक राजस्व घाटे को खत्म करना।
(b) केंद्र सरकार द्वारा RBI से कतिपय परिस्थितियों के सिवाय उधार न लेना।
(c) राजकोषीय वर्ष 2008–09 की समाप्ति तक प्राथमिक घाटे को खत्म करना।
(d) सरकारी गारंटियों को किसी भी वित्तीय वर्ष में सकल घरेलू उत्पाद (GDP) की प्रतिशतता के रूप में नियत करना।

11. राष्ट्रीय निवेश निधि, जिसमें विनिवेश प्राप्तियाँ पहुँचती हैं, के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिये: **UPSC (Pre) 2010**
1. केंद्रीय वित्त मंत्रालय राष्ट्रीय निवेश निधि की परिसंपत्ति का प्रबंधन करता है।
2. राष्ट्रीय निवेश निधि भारत की संचित निधि के अंतर्गत रखी जाती है।
3. कुछ परिसंपत्ति प्रबंधन कंपनियाँ निधि प्रबंधकों के रूप में नियुक्त की जाती हैं।
4. वार्षिक आय का निश्चित अनुपात चुनिंदा सामाजिक क्षेत्रों का वित्तपोषण करने के लिये प्रयुक्त होता है।
उपर्युक्त में से कौन-सा/से कथन सही है/हैं?
(a) 1 और 2 (b) केवल 2
(c) 3 और 4 (d) केवल 3

उत्तरमाला

1. (c) 2. (c) 3. (d) 4. (a) 5. (c) 6. (a) 7. (d) 8. (b) 9. (d) 10. (c)
11. (c)

दीर्घउत्तरीय प्रश्न

1. उत्तर-उदारीकरण अवधि के दौरान, बजट निर्माण के संदर्भ में, लोक व्यय प्रबंधन भारत सरकार के समक्ष एक चुनौती है। इसको स्पष्ट कीजिये। **UPSC (Mains) 2019**
2. 2017–18 के संघीय बजट के अभीष्ट उद्देश्यों में से एक उद्देश्य 'भारत को रूपांतरित करना, ऊर्जावान बनाना और भारत को स्वच्छ करना' है। इस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिये बजट 2017–18 में सरकार द्वारा प्रस्तावित उपायों का विश्लेषण कीजिये। **UPSC (Mains) 2017**
3. भारत में महिला सशक्तीकरण के लिये जेंडर बजटिंग अनिवार्य है। भारतीय प्रसंग में जेंडर बजटिंग की क्या आवश्यकताएँ एवं स्थिति हैं? **UPSC (Mains) 2016**
4. वित्तीय दायित्व और बजट प्रबंधन (FRBM) अधिनियम 2003 को प्रारंभ करने के क्या कारण थे? उसके प्रमुख प्रावधानों और उनकी प्रभाविता का समालोचनात्मक विवेचन कीजिये। **UPSC (Mains) 2013**
5. लोक वित्त के विभिन्न पहलुओं को स्पष्ट करते हुए उन आधारों को बताइये जिन आधारों पर यह निजी वित्त से अलग होता है।
6. किसी देश की राजकोषीय नीति उसके आर्थिक विकास की दिशा तथा दशा को निर्धारित करती है। इस कथन के आलोक में राजकोषीय नीति के उद्देश्यों को स्पष्ट कीजिये।
7. भारत में जेंडर बजटिंग की शुरुआत वित्तीय वर्ष 2005–06 के आम बजट से की गई। इसकी अब तक की उपलब्धियों का समालोचनात्मक मूल्यांकन कीजिये।
8. हाल के वर्षों में भारत ने अपने बजट में कुछ महत्त्वपूर्ण सुधार किये हैं। इन सुधारों को स्पष्ट करते हुए इनके संभावित प्रभावों का उल्लेख कीजिये।

अध्याय
7

कर संरचना
(Tax Structure)

7.1 कर
7.2 कर के उद्देश्य
7.3 कराधान के सिद्धांत
7.4 कराधान की प्रणाली
7.5 शब्दावली
7.6 लैफर वक्र
7.7 करों का वर्गीकरण
7.8 भारतीय कर व्यवस्था
7.9 प्रत्यक्ष कर
7.10 अप्रत्यक्ष कर
7.11 मूल्य-वर्द्धित कर
7.12 कर सुधार
7.13 वस्तु एवं सेवा कर
7.14 जीएसटी से संबंधी विवाद
7.15 ई-वे बिल
7.16 राष्ट्रीय मुनाफाखोरी विरोधी प्राधिकरण
7.17 रिवर्स चार्ज
7.18 कर प्रशासन सुधार आयोग की रिपोर्ट

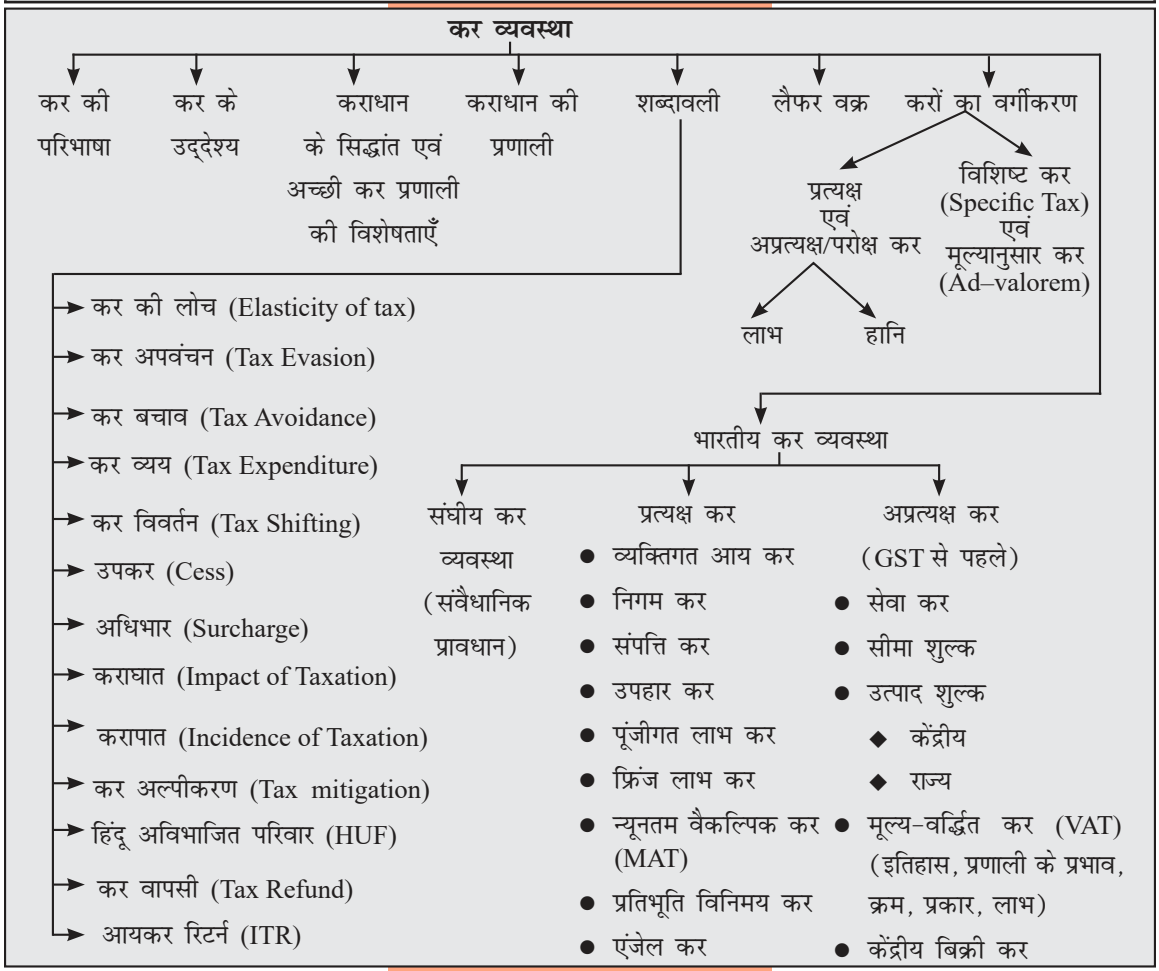

अध्याय
8

आयोजन (Planning)

8.1 अवधारणा
8.2 आयोजन की आवश्यकता क्यों?
8.3 आयोजन के प्रकार
8.4 भारत में आयोजन
8.5 योजना आयोग एवं राष्ट्रीय विकास परिषद
8.6 भारत में पंचवर्षीय योजनाएँ
8.7 इंडिया विज़न-2020
8.8 सरकार की प्रमुख योजनाएँ एवं कार्यक्रम
8.9 भारत में आयोजन का आलोचनात्मक मूल्यांकन
8.10 नीति आयोग
8.11 नीति आयोग का तीन वर्षीय एक्शन एजेंडा 2017–18 से 2019–20
8.12 दीर्घकालिक दस्तावेज़
8.13 त्रिवर्षीय एक्शन प्लान (संक्षेप में)

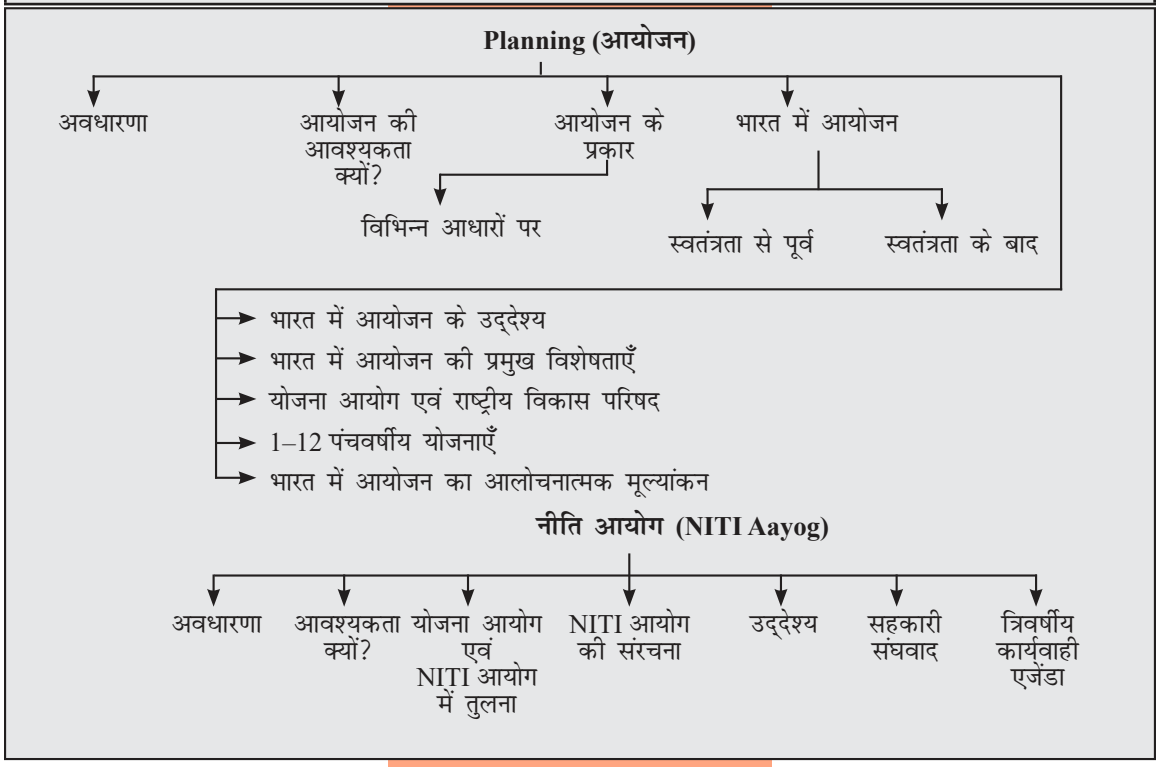

8.1 अवधारणा *(Concept)*

राज्य के नेतृत्व में संपूर्ण अर्थव्यवस्था का ऐसा प्रबंधन जिससे राष्ट्रहित की प्राप्ति हेतु उपलब्ध संसाधनों का अनुकूलतम उपयोग (Optimum Utilization) सुनिश्चित हो सके। साथ ही दीर्घकालिक निरंतरता (Long-Term Continuity) सुनिश्चित हो सके, आर्थिक आयोजन कहलाता है। इसे आयोजना, आर्थिक नियोजन एवं योजना-निर्माण आदि नामों से भी जाना जाता है।

कल्याणकारी राज्य (Welfare State) में आर्थिक नियोजन द्वारा समाज को विकसित करने का लक्ष्य रखा जाता है। लगभग 200 वर्षों के अंग्रेज़ी शासन के दौरान भारत की अर्थव्यवस्था को जान-बूझकर अल्पविकसित बनाने के उद्देश्य से ब्रिटेन की अर्थव्यवस्था के साथ इस तरह जोड़ दिया गया था कि भारत की अर्थव्यवस्था पूरी तरह से ब्रिटेन की अर्थव्यवस्था

अध्याय
9

निवेश मॉडल एवं पूंजी निर्माण
(Investment Model and Capital Formation)

9.1 निवेश की अवधारणा
9.2 निवेश एवं बचत में संबंध
9.3 पूंजी-उत्पाद अनुपात
9.4 वर्द्धमान पूंजी-उत्पाद अनुपात
9.5 वर्द्धमान पूंजी-उत्पाद अनुपात तथा पूंजी-उत्पाद अनुपात में संबंध
9.6 मानव पूंजी निर्माण
9.7 निवेश मॉडल
9.8 सार्वजनिक-निजी सहभागिता (पीपीपी) निवेश मॉडल
9.9 पीपीपी मॉडल की विभिन्न व्यवस्थाएँ
9.10 पीपीपी मॉडल के लाभ
9.11 विशेष प्रयोजन वाहन
9.12 राष्ट्रीय निवेश एवं आधारिक संरचना कोष
9.13 व्यवहार्यता/अर्थक्षमता अंतर वित्तपोषण
9.14 हाइब्रिड एन्यूटी मॉडल
9.15 स्विस चैलेंज मॉडल
9.16 अभियांत्रिकी, खरीद और निर्माण मैनेजमेंट मॉडल
9.17 सार्वजनिक-निजी भागीदारी मॉडल को पुनर्जीवित करने के लिये डॉ. विजय केलकर समिति
9.18 विनिवेश

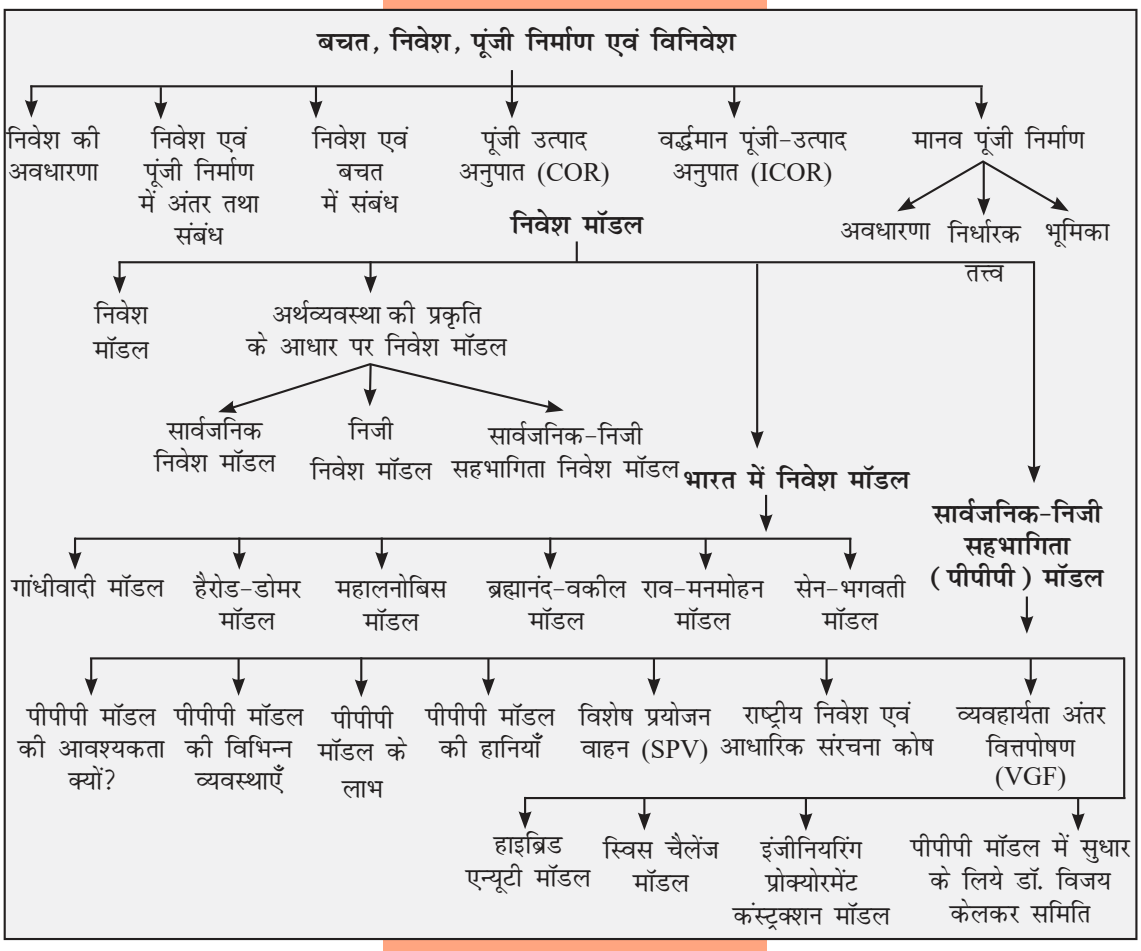

अध्याय
10

श्रम सुधार एवं जनांकिकीय (Labour Reform and Demographic)

10.1 श्रम क्या है?
10.2 श्रम की विशेषताएँ
10.3 शब्दावली
10.4 भारत में श्रम की स्थिति
10.5 श्रम सुधार की आवश्यकता क्यों?
10.6 श्रम सुधार के लिये सरकार के प्रयास
10.7 श्रम क्षेत्र से संबंधित प्रमुख कानून और अधिनियम
10.8 श्रम कानूनों में सुधार
10.9 जनांकिकी अवधारणा
10.10 जनसंख्या
10.11 जनसंख्या संबंधित सिद्धांत
10.12 कार्यशील जनसंख्या एवं जनांकिकीय लाभांश
10.13 जनसंख्या पिरामिड
10.14 जनसंख्या से संबंधित पारिभाषिक शब्द
10.15 भारत की जनसंख्या नीति
10.16 राष्ट्रीय जनसंख्या नीति, 2000
10.17 भारत में जनगणना
10.18 सामाजिक-आर्थिक और जातिगत जनगणना-2011
10.19 भारत की जनगणना-2011 के प्रमुख आँकड़े

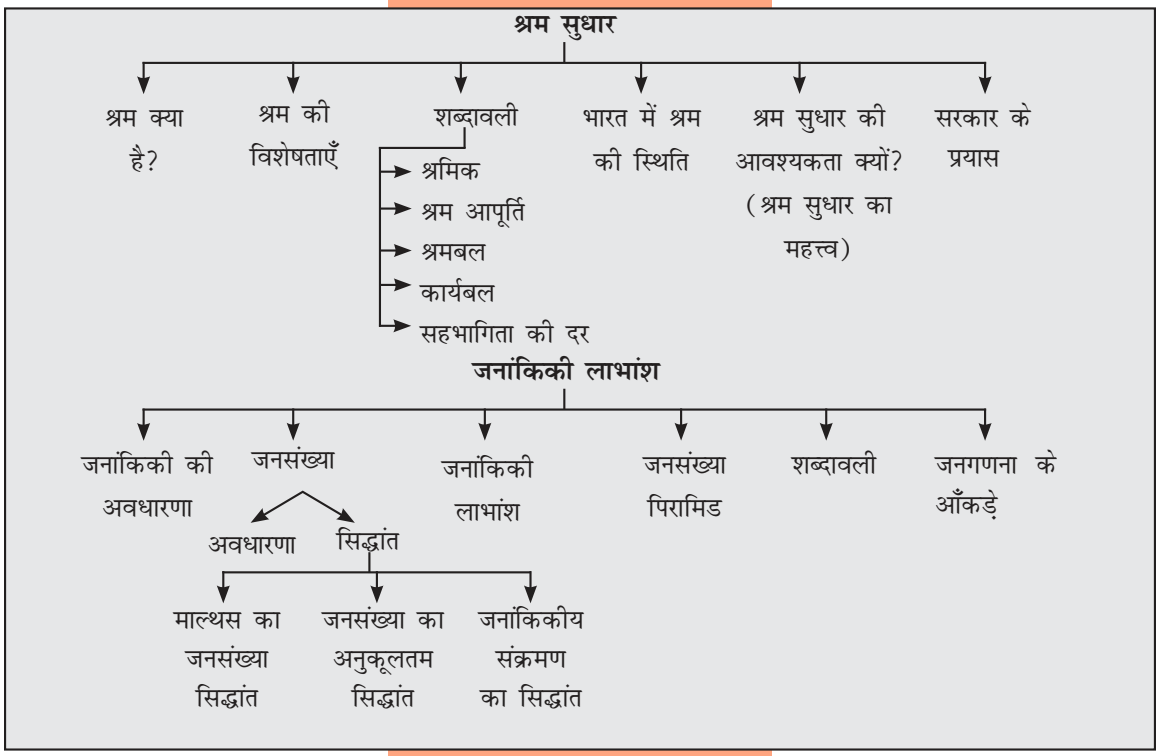

10.1 श्रम क्या है? *(What is Labour)*

- मानव के कुल शारीरिक और मानसिक प्रयास जो वस्तु एवं सेवाओं के निर्माण में उपयोगी होते हैं, श्रम कहलाता है।
- श्रम, उत्पादन का एक प्राथमिक कारक है।

अध्याय
11

व्यष्टि अर्थशास्त्र
(Micro Economics)

11.1 मांग का सिद्धांत
11.2 मांग का नियम
11.3 उपभोक्ता के व्यवहार का सिद्धांत
11.4 आपूर्ति का सिद्धांत
11.5 उत्पादन का सिद्धांत
11.6 राजस्व/संप्राप्ति की अवधारणा
11.7 लागत का सिद्धांत
11.8 बाज़ार के विभिन्न रूप

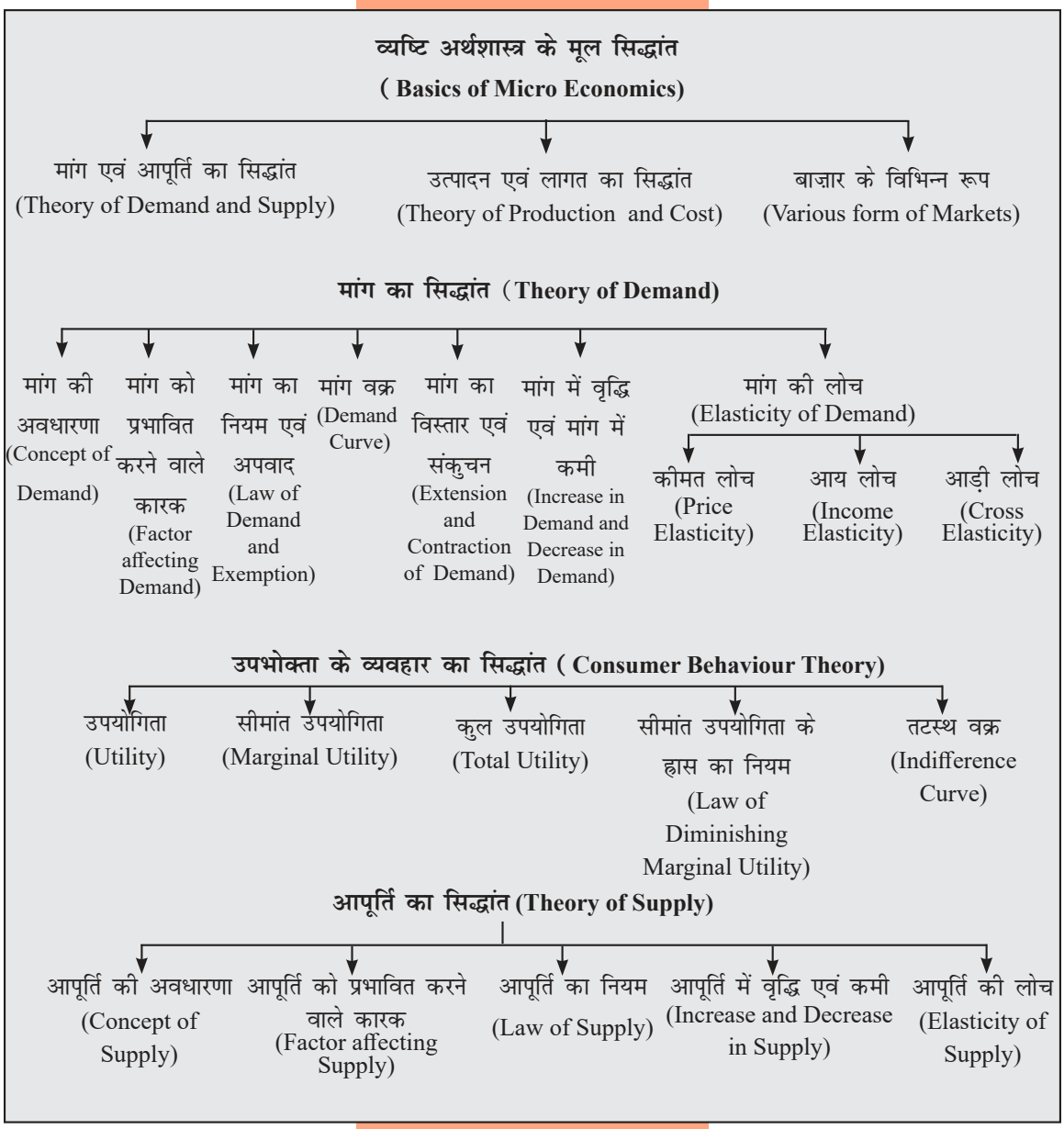

अध्याय
12

पूंजी बाज़ार
(Capital Market)

12.1 व्यवसाय, पेशा एवं रोज़गार में अंतर
12.2 वाणिज्य एवं व्यापार में अंतर एवं संबंध
12.3 व्यवसाय संगठन
12.4 कंपनी क्या है?
12.5 कंपनियों के प्रकार
12.6 शेल कंपनी
12.7 कंपनी की पूंजी
12.8 कंपनी अधिनियम, 1956
12.9 कंपनी अधिनियम, 2013
12.10 भारतीय कंपनियों की वर्तमान स्थिति
12.11 सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम
12.12 पूंजी बाज़ार
12.13 प्रतिभूति बाज़ार
12.14 स्टॉक एक्सचेंज
12.15 मसाला बॉण्ड
12.16 भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड
12.17 शब्दावली
12.18 डेरिवेटिव्स का परिचय
12.19 भारत में साझा कोष
12.20 अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसीप्ट (ADR), ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसीप्ट (GDR) तथा इंडियन डिपॉजिटरी रिसीप्ट
12.21 एंजल निवेशक
12.22 साख निर्धारण
12.23 बीमा
12.24 बीमा लोकपाल नियम, 2017
12.25 कमोडिटी बाज़ार
12.26 वायदा बाज़ार

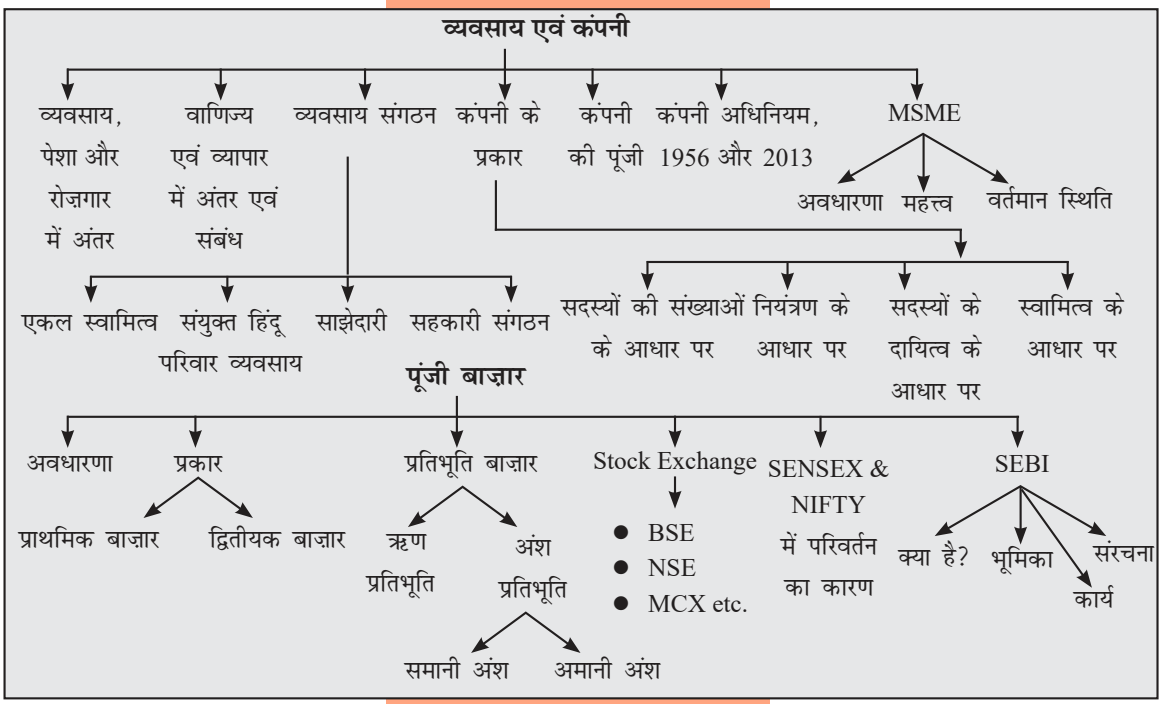

डी.एल.पी. बुकलेट्स की विशेषताएँ

- आयोग के नवीनतम पैटर्न पर आधारित अध्ययन सामग्री।
- पैराग्राफ, बुलेट फॉर्म, सारणी, फ्लोचार्ट तथा मानचित्र का उपयुक्त समावेश।
- विषयवस्तु की सरलता, प्रामाणिकता तथा परीक्षा की दृष्टि से उपयोगिता पर विशेष ध्यान।
- क्विक रिवीजन हेतु प्रत्येक अध्याय में महत्त्वपूर्ण तथ्यों का संकलन।
- प्रत्येक अध्याय के अंत में विगत वर्षों में पूछे गए एवं संभावित प्रश्नों का समावेश।

Website : www.drishtiIAS.com
E-mail : online@groupdrishti.com

DrishtiIAS
YouTube Drishti IAS
drishtiias
drishtithevisionfoundation

641, First Floor, Dr. Mukherjee Nagar, Delhi-110009
Phones : 8750187501, 011-47532596